>

Title: Regarding need for adequate storage facilities for food grains in the country.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मान्यवर, देश में बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल पैदा हुई है। आज से चार दिन पहले भी मैंने इस सवाल को यहां उठाया था और उसके पहले सुषमा जी ने भी इसे उठाया था। उस समय प्रणब बाबू यहां मौजूद थे और आज भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को शून्य काल में उठाने का मौका दिया है, चूंकि यह इतना विस्तृत मुद्दा है कि इस पर सदन में नियम 193 के तहत बहस कराने का एश्योरेंस आसन की तरफ से आना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि धान का उत्पादन इस बार 10.34 करोड़ टन हुआ है, वह मामला तो चला गया। इस बार गेंहू का रिकार्ड उत्पादन करीब 9.02 करोड़ टन हुआ है, जैसा कि सरकार ने बताया है। आपकी स्टोरेज केपेसिटी केवल 19 फीसदी है।

देश के 40 करोड़ किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में किसानों ने पूरी ताकत लगाकर यह अनाज पैदा किया है। हमारे देश में गरीबों की बहुत बड़ी तादाद है। महाराष्ट्र में लातूर, उस्मानाबाद और देश के कई इलाकों में सूखा पड़ा है, पानी तक की किल्लत है। ऐसी परिस्थति हमारी सरकार के समय भी आई थी, जब मैं फूड एंड कन्ज्युमर मामलों के विभाग का मंत्री था। उस समय देश के सात सूबों में सूखा पड़ा था। अनाज की किल्लत हमारे सामने भी आई थी। पशुओं के चारे के लिए और फ्लोर मिल्स के लिए हम लोगों ने सूखाग्रस्त इलाकों में अनाज भेजा था। आडवाणी जी की अगुवाई में एक क्राइसेज़ मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। मुझे याद है कि राजस्थान में हम लोगों ने एक लाख मीट्रिक टन अनाज बिना पैसे के दिया था। सरकार की भी रिपोर्ट है, सदन के सभी सदस्य कहते हैं और मीडिया में भी आ रहा है कि अनाज के ढेर खुले आसमान के नीचे लगे हुए हैं। पंजाब में जमीन की कीमतें ज्यादा होने के कारण वहां गोदाम बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है। आपने 2009 में कई जगह गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन आपके विभाग से अभी तक कोई सब्सिडी रिलीज नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर किसान अपनी फसल के स्टोरेज के लिए अपनी जमीन पर और अपने साधनों को आगे-पीछे करके यह काम कर रहे हैं।

हमने बिहार में अभी फैसला किया है कि प्रदेश सरकार 50 फीसदी सब्सिडी गोदाम बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे देगी। आज के समय में बाजार एक भी चीज में आगे नहीं सरक रहा है, पीछे ही जा रहा है। दुनिया के कई मुल्क हमारे बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ नीचे जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पीछे हो गई है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और आयात-निर्यात पर असर पड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने, इन 3 वर्षों में, आप कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हिला, बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, हिंदुस्तान के बैंक और हिंदुस्तान के किसानों ने सबसे ज्यादा इसके लिए काम किया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your point.

...(*Interruptions*)

श्री शरद यादव: अर्जुन सेन गुप्ता की बात जब भी आती है, आप लोग कहते हैं कि गलत बात है, मैं कहता हूं कि वह अकेला आदमी था जो सच बोलकर गया है, आज वह नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। आज हालत यह है कि गरीबों की संख्या रोज बढ़ती जाती है। आपके पास अनाज है तो आप क्यों नहीं सबसे पहले क्राइसेज ग्रुप बनाते हैं? सोनिया जी, यह जो सारा मामला है, देश में क्या हालत है, इसे आप समझ नहीं रही हैं। आज सब जगह सड़कों पर गेहूं पड़ा है, रखने की जगह नहीं है, कभी भी बारिश हो जाएगी तो सारा गेहूं खराब हो जाएगा। दिल्ली में मौसम ठीक हो जाता है लेकिन 450 किलोमीटर के गेहूं के इलाके में किसानों की बर्बादी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं लेकिन सरकार तो इस पर विश्वास भी नहीं करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जरा सी खबर आई थी।

माननीय प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि इस बारे में मीटिंग बुलाएं। जो समस्या आपके हाथ में नहीं है उसका क्या करोगे लेकिन जो समस्या आपके हाथ में है उस पर कोई रास्ता बनाइये। मैं जब फूड मिनिस्टर था, मैं कंज्यूमर मिनिस्टर था तो प्रणब बाबू मैं रोज गांव में जो समस्या थी उसको अपने सामने रखता था और खास करके गरीबों की जो मोटी चीजें खाने की हैं उनको सामने रखता था। सबसे पहली जरूरत गरीबों की पेट है, वह सबसे पहले आटा चाहता है, चावल चाहता है। आपके पास चावल है, आपके पास गेहूं है, पूरे देश में अनाज पड़ा सड़ रहा है, खराब हो गया है तो क्यों नहीं उनकी समस्या को आप दूर करते हैं।

किसानों ने सारी दिक्कतों के बावजूद, भोजन के मामले में, उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उनकी समस्या के ऊपर आपको सबसे पहले इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट कीजिए। आपने जूट और कपास के एक्सपोर्ट का फैसला किया। मैं इस पर आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और वे ऐसे लोग हैं जो आपके सिर पर डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन गेहूं का गरीब किसान क्या करेगा, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, वह कहां जाए? आप यहां चार दिन पहले बैठे हुए थे आपने इस बात का जवाब नहीं दिया और चले गये। आपकी सरकार में इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, आप इस पर क्या करेंगे, सारा सदन इस पर चिंतित है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री शरद यादव : यहां सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि इस पर बोलने के लिए इन्हें समय नहीं दिया जाता है। मैं बाहर निकलूंगा तो सब मुझे कहेंगे...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी को बुलाइये, क्या करेंगे आप इस पर, क्या रास्ता निकालेंगे। क्यों नहीं इस मामले को शीघ्र ही हाथ में लेते हैं। ...(व्यवधान) सरकार के हाथ से एक-एक चीज निकलती जा रही है, एक-एक मामला हाथ से जा रहा है। आप सब चीजों को देखिये।...(व्यवधान) सभापति जी, आप गोवा के हैं, आपको पता नहीं है कि इस इलाके में क्या तबाही मची हुई है। सब जगह तबाही है, आप पंजाब चले जाइये, वहां पर खुले में गेहूं के पहाड़ जैसे ढेर दिखाई देते हैं। आप बताइये, किसान कहां जाए?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your point. Please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री शरद यादव: हम चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर निपटा दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Please do not disturb.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : धन्यवाद सभापति जी, मैं गेहूं पर ही बोल रही हूं।

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the submission being made by Shrimati Sushma Swaraj.

(Interruptions) â€¦*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अभी शनिवार-रविवार को मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके वापस लौटी हूं और आंखों देखी कहानी इस सदन में सुनाना चाहती हूं। पूरे मध्य प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद का इतना उत्तम प्रबंध किया था। *(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record, except what Shrimati Sushma Swaraj is saying.

(Interruptions) â€¦*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, हमने किसानों का पूर्व पंजीयन कराया, एसएमएस करके किसानों को बुलाया और उनका पूरा गेहूं तुलवा कर एकाउंट में पैसे दे दिए। यह व्यवस्था तब तक चलती रही, जब तक हमारे पास बोरियां उपलब्ध थीं। लेकिन अचानक एक दिन बोरियों की उपलब्धता खत्म हो गई। बोरियां न होने के कारण पूरी व्यवस्था बैठ गई। जैसा शरद जी ने कहा कि पूरा गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है और किसान वहां रात भर खड़ा रह कर पहरेदारी कर रहा है। दो बार पानी गिर चुका है और दस-दस मिनट पानी गिरने के कारण पूरा का पूरा गेहूं खराब हो गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Shrimati Sushma Swaraj is saying.

*(Interruptions)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली आए और फूड मिनिस्टर से मिले। उन्होंने मेरे सामने यह आश्वासन दिया कि 46 हजार गठानें 5 मई तक दे देंगे। प्रणब दादा 5 मई बीत चुकी है और आज 7 मई है, अभी 11 हजार गठानें 46 हजार गड्डानों में से आनी बाकी हैं तथा 50 हजार और गठानें उन्होंने 20 मई तक देने की बात कही थी। 96 हजार गठानें, जिनका पैसा पड़ा हुआ है, 2 लाख 69 हजार गठानों का 478 करोड़ रुपया हमने अग्रिम राशि के रूप में जमा कराया हुआ है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं, न रैक लगे हैं, न लोड हुए हैं और हमारे पास बोरियां नहीं हैं। बोरियों के न होने की वजह से पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। किसान रो रहा है। पिछली बार हमने आपको 50 लाख मिट्रिक टन गेहूं दिया था, लेकिन इस बार 80 लाख मिट्रिक टन गेहूं हम आपको देने वाले हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि केवल बोरियां न होने की वजह से किसान का गेहूं तुल नहीं पा रहा है। अगर बोरी पहुंचती है, तो किसान रैक में से बोरी की लूटपाट कर रहा है। किसान वहां बैठ कर सारी रात पहरेदारी कर रहा है और अगर दस-दस मिनट का पानी गिर जाता है, तो छाती पीट-पीट कर रो रहा है, क्योंकि जब उसका गेहूं तोला जाएगा, तो कहा जाएगा कि गेहूं खराब हो गया है।

सभापति महोदय, मैं प्रणब दा से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ बोरियां चाहिए, आप बोरियां दे दीजिए, हमारा किसान मरने से बच जाएगा, क्योंकि गेहूं तुल जाएगा और आपके पास सैंटर पूल में हम वह गेहूं आपको दे देंगे। कृपया आप हमें बोरियां दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Rest of the Members may please associate with what the hon. Member has said. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There will be no more discussion. Other hon. Members may associate with the hon. Member who raised the issue.

योगी आदित्यनाथ।

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Others may kindly associate. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

सभापति महोदय :

श्री पी.के. बिजू,

श्री अर्जून राम मेघवाल,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री पी.एल. पुनिया,

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला,

श्री महेन्द्र पी. चौहाण,

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल,

श्री शिवराज भैया,

श्री जीतेन्द्र सिंह,

श्री भूपेन्द्र सिंह,

श्री राकेश सिंह,

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला,

श्री नामा नागेश्वर राव एवं

श्री धनंजय सिंह को शरद यादव जी एवं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध किया जाता है।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only the statement of hon. Member Yogi Aditya Nath will go on record and nothing else.

*(Interruptions)**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The point has already been made. Please sit down.

*(Interruptions)**

योगी आदित्यनाथ: प्रति वर्ष कैलाश मानसरोवर की पवित्र धार्मिक यात्रा देश के अंदर आयोजित की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, यह यात्रा 26 दिन की होती है, जिसे कुमाऊँ मण्डल विकास निगम आयोजित करती है। भारत और तिब्बत की सीमा तक तीर्थ यात्रियों के आने और जाने की व्यवस्था करती है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Yogi Aditya Nath is saying. Please continue.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: You cannot compel the Government during the 'Zero Hour'. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Do not disturb him.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 12.30 pm.

12.20 hrs

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, Shri Sharad Yadav ji, Shrimati Sushmaji, the Leader of the Opposition and many other Members want to speak on this issue. This year we made a record production of both wheat and rice. Our genuine problem is with regard to the storing facilities of that quantum of procurement, which is taking place. In earlier days, the Government used to procure about 30 to 40 per cent of the total production and the rest of

the production was taken care of by the market. But in the last two, three years because of the high MSP, procurement has become the primary responsibility of the Government agencies, whether it is the State Governments or it is the Central Government. The FCI is also authorizing and requesting the State Governments to purchase it. But, the creation of the godown space is not keeping a match with the rate of procurement. There is a mismatch. But we are trying to sort out this issue.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): कब तक होगा?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, it will take some time. Please have some patience. I am equally concerned about it because I am paying Rs.50,000 crore food subsidy. Therefore, I am equally concerned as you are concerned. As you are the concerned Member of Parliament to protect the public interest, as Finance Minister and the Treasurer of the country, I am concerned because it is going from my Treasury. Therefore, what we are trying to do is this. I am trying to get jute bags to provide the facilities and to address the problems which the Leader of the Opposition raised that jute bags are not available.

As per the practice, we do not allow plastic baggage to be used for food items because jute bags are bio-degradable packaging material which are universally acclaimed and should be used as the packaging material for food items. Therefore, in our system, rice, wheat and sugar, these three items are supplied in jute bags. As there has been shortage of jute bags, we are trying to augment the supply of jute bags. We are taking it up with the IJMA. It has already been taken up. We are also taking it up with other neighbouring countries from where we can import jute bags on urgent basis.

We are also requesting to dispose of the existing stock. For instance, the Chief Minister of Karnataka came and met me the other day. They require about five to eight lakh tonnes of food grains to meet their drought relief requirement. We have readily agreed to supply this quantum of food grains. We have allowed extra export so that the existing stock could be released. We are also requesting and we have already made arrangements with the Rural Development Ministry. They are taking some time because the State Governments are involved in it so that we can use food grains as part of the wages for the Government programmes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and all the measures are simultaneously being taken to ease the pressure which is being built up. But there is a question about it. There is no doubt that there is a mismatch. The other day, while replying to the General Discussion on the Budget, I gave detailed account of how in the last four, five years, we have created more than two million tonnes of storing capacity. We are giving series of tax concessions and investment concessions to create cold-chain facilities, to create warehousing and asking the private sector to participate in for that. Shri Sharad Yadavji has referred to some sort of subsidy scheme. I will definitely check up. If the Government made any commitment to pay subsidy, the Government will pay subsidy. So far as tax concessions are concerned for the last three years I am providing tax concessions, series of concessions, sometimes interest concessions, to create cold chains, to create warehousing, so that these problems can be tackled on a permanent basis, and neither the farmers nor those who are procuring, the Government agencies, State agencies, are in difficulty.

I appreciate the concerns the Hon. Members have expressed. I will check it up with my colleague in the Ministry of Food who is directly in charge of this, and Agriculture Ministry. I will give you the detailed information about the measures which have been taken in the course of my reply to the debate on the Finance Bill tomorrow. Thank you....(*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह (सतना): गेहूं की खरीदी का समय ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No more discussion on this.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति जी, ज़ीरो ऑवर का मेरा दूसरा मैटर है।

MR. CHAIRMAN: I cannot allow you now. Now we have Bills to be taken up.

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा?

MR. CHAIRMAN: You will get a chance when it will be taken up at the end of the day.

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मेरा एक मैटर है। स्पीकर महोदया ने सुबह कहा था ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You will get chance at the end of the day.